मार्च 2025

ऊर्जस्विनी

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड की त्रैमासिक पत्रिका

संरक्षक

श्री पंकज कुमार पाल

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक,
बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कं. लि.

परामर्श मंडल

श्री महेन्द्र कुमार

प्रबंध निदेशक,
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कं. लि. एवं
बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कं. लि.

डॉ. निलेश रामचंद्र देवरे

प्रबंध निदेशक,
नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कं. लि. एवं
बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कं. लि.

सदस्य

श्री अजय कुमार मिश्र

विशेष कार्य पदाधिकारी,
(मानव संसाधन एवं प्रशासन)
बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कं. लि.

श्रीमती साक्षी

सहायक कार्यपालक अभियंता,
बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कं. लि.

श्रीमती सुप्रिया सिन्हा

लेखा पदाधिकारी,
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कं. लि.

श्री राहुल कुमार

सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधक,
बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कं. लि.

श्री रजनीश कुमार 'गौरव'

कार्यालय अधीक्षक,
नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कं. लि.

संपादकीय

बिहार, जो कभी देश के ऊर्जा मानचित्र पर एक चुनौतीपूर्ण राज्य के रूप में देखा जाता था, वह आज ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलावों का साक्षी बन रहा है। ऊर्जस्विनी का यह विशेषांक न केवल इन उपलब्धियों का एक संक्षिप्त विवरण है, बल्कि उन दूरदर्शी नीतियों, नवाचारों और जनकल्याणकारी योजनाओं का संकलन भी है जिन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार को आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर किया है।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान दुर्गम क्षेत्रों में ऑन–ग्रिड विद्युतीकरण योजना की आधारशिला रखा जाना इस बात का प्रतीक है कि बिहार गुणवत्तापूर्ण बिजली को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की दिशा में संकल्पित है। माननीय ऊर्जा मंत्री के मार्गदर्शन में हमने बीते वर्षों में ऐसी कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया है, जो न केवल उत्पादन, संचरण एवं वितरण प्रणाली को सुदृढ़ कर रही हैं, बल्कि निवेशकों को भी आकर्षित कर रही हैं।

राज्य में हरित ऊर्जा की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं, इनमें प्रमुख रूप से सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विकास, सूर्य घर योजना और ऊर्जा भंडारण को बढ़ावा देना शामिल है। यह सभी कदम राज्य के कार्बन उत्सर्जन को घटाने एवं सतत् विकास के लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ने को परिलक्षित करते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हो रहे निवेश निश्चित ही बिहार को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर एवं अग्रणी बनाने में सहायक सिद्ध होंगे।

स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को ईटी गवर्नेंट डिजिटल अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया जाना गौरव की बात है। वितरण कंपनी को उपभोक्ता सेवा रेटिंग में ए ग्रेड प्राप्त करना और राज्य की ट्रांसमिशन कम्पनी को A+ श्रेणी मिलना यह सिद्ध करता है कि बिहार अब तकनीकी दक्षता और सेवा गुणवत्ता दोनों में अग्रणी बन रहा है।

बिजली आधारित कृषि क्रांति बिहार के किसानों को नई ऊर्जा दे रही है। सिंचाई में बिजली की सुविधा मिलने से कृषि लागत में कमी और उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त संचरण लाइनों के अनुरक्षण के लिए हॉटलाइन मेंटेनेंस तकनीक का पहली बार उपयोग राज्य में तकनीकी प्रगति का एक और मिसाल बन गया है।

बिहार में ऊर्जा की प्रगति यात्रा अब लोकसेवा, तकनीकी उत्कृष्टता एवं हरित भविष्य की सामूहिक प्रेरणा बन चुकी है। ऊर्जस्विनी का यह अंक न केवल उपलब्धियों का सारांश है, बल्कि भविष्य की दिशा का सकारात्मक संकेत भी है।

अनुक्रमणिका

1. प्रगति यात्रा से मिली प्रगति को नई ऊर्जा — 06
2. बिहार बिज़नेस कनेक्ट–2024 : नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करता बिहार — 10
3. हरित ऊर्जा की ओर तेज़ी से अग्रसर बिहार — 14
4. बैटरी ऊर्जा भण्डारण प्रणाली में बिहार अग्रणी राज्य — 16
5. राज्य में बिजली से हो रही नई कृषि क्रांति — 18
6. राज्य में 'पीएम सूर्य घर योजना' के लिए विशेष पहल — 22
7. पीरपैंती में 2400 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना की शुरूआत — 24
8. विद्युत राजस्व संग्रहण में बना नया कीर्तिमान — 26

अनुक्रमणिका

9. ऊर्जा प्रक्षेत्र में सम्मानों से गौरवान्वित बिहार	28
10. बिजली के बेहतर उपयोग के लिए आई–संचालित विश्लेषण को अपनाने में बिहार अव्वल	32
11. राज्य में पहली बार हॉटलाइन मेंटेनेंस के अभिनव तकनीक का प्रयोग	34
12. स्व0 अमरेन्द्र कुमार झा की स्मृति में समर्पित	35
13. फोटो गैलरी	36
14. सेवानिवृत सदस्यों का आभार...	40
15. खबरों में ऊर्जा	46

प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों ने 2024-25 में 17,114 करोड़ का रिकार्ड राजस्व संग्रह किया

मंत्री बोले- बिहार में उद्योग लगाएं, यहां काफी संभावनाएं

ऑन ग्रिड विद्युतीकरण योजना का मुख्यमंत्री ने किया शिलान्यास

प्रगति यात्रा से मिली प्रगति को नई ऊर्जा

बिहार ने बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में एक लंबा सफर तय किया है। राज्य सरकार ने हर घर तक बिजली पहुंचाने के बाद अब गुणवत्तापूर्ण और निर्बाधित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान विद्युत संरचनाओं के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जिन्हें धरातल पर उतारने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से उत्तर और दक्षिण बिहार में बिजली की उपलब्धता एवं संरचना में व्यापक सुधार होगा।

2312.93 करोड़ रुपये की विकास योजनाएं

माननीय मुख्यमंत्री की इस प्रगति यात्रा के दौरान राज्य में अब तक कुल 2312.93 करोड़ रुपये की विभिन्न विद्युत परियोजनाओं की घोषणाएं की जा चुकी हैं। उत्तर बिहार में 1323.92 करोड़ रुपये लागत की विद्युत ग्रिड सब–स्टेशन, विद्युत शक्ति उपकेंद्रों एवं सम्बद्ध लाईनों के निर्माण की योजना है, जबकि दक्षिण बिहार में 989.01 करोड़ रुपये लागत के विद्युत ग्रिड सब–स्टेशन, विद्युत शक्ति उपकेंद्र एवं सम्बद्ध लाईन स्थापित किए जाएंगे।

विद्युत संरचनाओं का व्यापक विस्तार

उत्तर बिहार के कई जिलों में विद्युत आपूर्ति को सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं की घोषणा की गई है:

- ✶ **पश्चिम चंपारण (अमुआमन, मंझौलिया)** : 148.49 करोड़ रुपये लागत की 132/22 kV, 2X80 MVA ग्रिड सब–स्टेशन का निर्माण।
- ✶ **सीतामढ़ी (मेजरगंज)** : 162.72 करोड़ रुपये लागत की 132/22 kV, 2X80 MVA ग्रिड सब–स्टेशन का निर्माण।
- ✶ **वैशाली (महुआ)** : 157.01 करोड़ रुपये लागत की 132/22 KV, 2X80 MVA ग्रिड सब–स्टेशन का निर्माण।
- ✶ **सीवान (मैरवा)** : 517.05 करोड़ रुपये लागत की 220/132/22 kV, 2X200 MVA+2X80 MVA ग्रिड सब–स्टेशन का निर्माण।
- ✶ **समस्तीपुर (वारिसनगर)** : 135.00 करोड़ रुपये लागत की 132/22 KV, 2X80 MVA ग्रिड सब–स्टेशन का निर्माण।
- ✶ **मधेपुरा (चौसा)** : 132.72 करोड़ रुपये लागत की 132/22 KV, 2X80 MVA ग्रिड सब–स्टेशन का निर्माण।

इसके अलावा वैशाली जिले में 35.13 करोड़ रुपये लागत की चार नए 33/11 KV, 2X10 MVA विद्युत शक्ति उपकेंद्रों का निर्माण किया जाएगा। ये उपकेंद्र महुआ, बेलसर, लालगंज और पातेपुर प्रखंडों में स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही मधेपुरा जिला अंतर्गत फुलौत (प्रखंड–चौसा) एवं अमारी धरहरा (प्रखंड– मुरलीगंज) में 25.99 करोड़ रुपये लागत की 33/11 kV 2X10 MVA विद्युत शक्ति उपकेंद्र का निर्माण व जिला किशनगंज अंतर्गत खगड़ा में 9.80 करोड़ रुपये लागत के नये 33/11 kV 2X10 MVA विद्युत शक्ति उपकेंद्र का निर्माण किया जाना है। साथ ही किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरपुर प्रखंड के लौचा में 2X10 MVA 33/11 kV नए विद्युत शक्ति उपकेन्द्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

दक्षिण बिहार में भी विद्युत आपूर्ति को मजबूत करने के लिए कई नई परियोजनाओं की घोषणा की गई है:

- ✶ **लखीसराय (हलसी, सिरखंडी)** : 182.69 करोड़ रुपये लागत की ग्रिड सब–स्टेशन का निर्माण।
- ✶ **नवादा (रोह)** : 191.26 करोड़ रुपये लागत की 132/22 kV, 2X80 MVA ग्रिड सब–स्टेशन का निर्माण।
- ✶ **बांका (अमरपुर)** : 227.93 करोड़ रुपये लागत की 132/22 kV, 2X80 MVA ग्रिड सब–स्टेशन का निर्माण।

- **बांका (बांसी और बेलहर)** : 12.48 करोड़ रुपये लागत की 33 kV लाइन का निर्माण।
- **बांका (मंदार पर्वत)** : 14.32 करोड़ रुपये लागत की 33/11 kV, 2X10 MVA विद्युत शक्ति उपकेंद्र का निर्माण।
- **लखीसराय (बड़हिया)** : 63.40 करोड़ रुपये लागत की 2X20 MVA ग्रिड सब–स्टेशन एवं 132 kV S/C लखीसराय–हाथीदाह संचरण लाइन का निर्माण।

पटना शहर में विद्युत प्रणाली का आधुनिकीकरण

राजधानी पटना में विद्युत वितरण की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए 296.93 करोड़ रुपये लागत की आधुनिकीकरण की योजना बनाई गई है। यह परियोजना बेहतर वितरण एवं विद्युत संरचना, नए शक्ति उपकेन्द्रों के निर्माण, उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मर की स्थापना एवं अंडरग्राउण्ड केबल प्रणाली पर केंद्रित है। इससे पटना और उसके आसपास के शहरी क्षेत्रों में अधिक गुणवत्तापूर्ण एवं स्थिर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

नवीन ऊर्जा युग की ओर अग्रसर बिहार

इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन से बिहार की विद्युत आधारभूत संरचनाओं में बड़ा बदलाव आएगा। राज्य सरकार का यह प्रयास राज्यवासियों को न केवल निर्बाध बिजली आपूर्ति देने में सहायक होगा, बल्कि औद्योगिक और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा। बिहार अब केवल विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में ही नहीं, बल्कि एक ऊर्जा सक्षम राज्य के रूप में उभरने की ओर भी तेजी से बढ़ रहा है।

पश्चिम चंपारण में ऑन ग्रिड विद्युतिकरण योजना का मुख्यमंत्री ने किया शिलान्यास

माननीय मुख्यमंत्री ने अपने प्रगति यात्रा के पहले दिन पश्चिम चंपारण जिले के घोटवा टोला (संतपुर सोहरिया पंचायत) से वाल्मीकि नगर क्षेत्र में 139.04 करोड़ रुपये की लागत से ऑफ ग्रिड से ऑन ग्रिड विद्युतीकरण योजना का शिलान्यास किया। इस परियोजना से मुख्यतः वाल्मीकि नगर के दुर्गम घने जंगली इलाकों में निवास कर रहे थारु जनजाति के परिवारों को ग्रिड के माध्यम से निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होगी जिससे उन ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी गति मिलेगी। विदित है कि इन इलाकों में अभी सौर ऊर्जा के संयंत्रों से बिजली मिलती है जिसको इस परियोजना के तहत अब अंडर ग्राउंड केबल के माध्यम से जंगलों में तथा टॉवर पर गंडक नदी पार करा कर ग्रिड से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इससे इन दुर्गम घने जंगल के इलाकों में भी लोगों को 24X7 बिजली उपलब्ध हो सकेगी।

इस परियोजना के तहत 25 गांवों के 11,798 घरों को ऑफ ग्रिड से ऑन ग्रिड विद्युत आपूर्ति में परिवर्तित किया जाएगा। इस योजना से क्षेत्र में निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में सुधार होगा।

योजना के तहत सरकारी स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों को भी विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। परियोजना को 18 महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

योजना की कुल लागत 139.04 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 60.17 करोड़ रुपये और शेष 78.87 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

बिहार बिज़नेस कनेक्ट-2024 : नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करता बिहार

बढ़ती आबादी की वजह से प्रतिदिन देश और दुनिया में बिजली की मांग बढ़ती ही जा रही है। लेकिन यह भी सत्य है कि प्रकृति के संसाधन सीमित हैं। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देना जरूरी है, ताकि आने वाले समय में ऊर्जा के अन्य स्रोतों को रेखांकित और विकसित किया जा सके। समय की मांग को देखते हुए बिहार नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में न सिर्फ मजबूती से कदम बढ़ा रहा है बल्कि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश को भी आकर्षित कर रहा है।

बिहार बिज़नेस कनेक्ट–2024 के दौरान सबसे अधिक निवेश के लिए एकरारनामा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हुआ है।

इस क्षेत्र में 90,734 करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव मिले, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि उत्साहजनक निवेश के साथ बिहार इस क्षेत्र में एक नया इतिहास लिख रहा है।

गौरतलब है कि बिहार बिज़नेस कनेक्ट-2024 के दौरान सन पेट्रो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने रिन्युएबल एनर्जी के क्षेत्र में पंप स्टोरेज एवं सोलर प्रोजेक्ट के लिए ₹36,700 करोड़, एनएचपीसी ने सोलर प्लांट के लिए ₹5,500 करोड़, एनटीपीसी ग्रीन ने रिन्युएबल सोलर प्लांट के लिए ₹10,000 करोड़, एसजेवीएन ने पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए ₹10,000 करोड़ एवं अन्य कम्पनियों ने निवेश की सहमति दी है।

बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 90,734 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों और समझौतों के साथ राज्य ने सतत् विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस पहल ने राज्य को स्वच्छ ऊर्जा और हरित भविष्य के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में से एक के रूप में स्थापित करने की दिशा में मजबूती प्रदान की है। बिहार के पास जलमग्न क्षेत्रों का एक बड़ा भौगोलिक परिदृश्य है, जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट परियोजनाओं के लिए आदर्श हैं। इस तकनीक का उपयोग न केवल ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि जल वाष्पीकरण को भी कम करेगा और जल स्रोतों का संरक्षण करेगा। इन परियोजनाओं के कई लाभ हैं। भूमि की आवश्यकता समाप्त होगी, जिससे कृषि भूमि संरक्षित रहेगी। जल स्रोतों का कुशल उपयोग और ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि के साथ ही पर्यावरण संरक्षण और सतत् विकास संभव हो सकेगा। बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों, तालाबों, नहरों और जलाशयों को फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं के लिए उपयुक्त माना जा रहा है।

बिहार में पंप स्टोरेज परियोजनाओं को लागू करने के लिए शुरुआती सर्वेक्षण पूरे कर लिए गए हैं। कैमूर और नवादा जिले में संभावित स्थानों की पहचान की गई है। ये परियोजनाएं न केवल बिजली उत्पादन को स्थिर बनाएंगी, बल्कि ग्रिड प्रबंधन में भी सहायक होंगी।

बिहार में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास की अपार संभावनाएं हैं। बिहार के जल स्रोतों और भौगोलिक स्थिति का उपयोग कर हम नवीकरणीय ऊर्जा में एक नई क्रांति ला सकते हैं।

सोलर और पंप स्टोरेज योजनाएं बिहार में हरित ऊर्जा के नए युग की शुरुआत करेंगी। इन परियोजनाओं से हजारों रोजगार सृजित होंगे एवं राज्य की ऊर्जा आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी। इसके साथ ही कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जो पर्यावरणीय संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार का हरित पहल राज्य को देश के हरित ऊर्जा केंद्र के रूप में स्थापित करने के साथ-साथ आर्थिक, औद्योगिक और पर्यावरणीय प्रगति को गति प्रदान करेगी। फ्लोटिंग सोलर और पंप स्टोरेज योजनाओं के साथ बिहार ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक मिसाल कायम करने के लिए तैयार है। यह राज्य को ऊर्जा आत्मनिर्भरता और हरित भविष्य की दिशा में ले जाने का एक बड़ा कदम है।

NESS
NECT
STORS' SUMMIT
20, 2024 | PATNA
BIHAR
BUSIN
CONN
2024
A GLOBAL INVEST
DECEMBER 19 - 2

हरित ऊर्जा की ओर तेज़ी से अग्रसर बिहार

एक दशक पहले तक सौर ऊर्जा राज्य में महज़ एक सपना था आज वह ज़मीनी हकीकत है। अब गांव की गलियों में सोलर स्ट्रीट लाइट की रोशनी फैली हुई है। खेतों में किसान सोलर पंप की मदद से सिंचाई कर रहे हैं और स्कूलों, अस्पतालों और पंचायत भवनों की छतों पर सौर पैनल से रोशनी मिल रही है।

सिर्फ परियोजनाएँ नहीं, परिवर्तन की लहर

राज्य सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और नीति-निर्माण के साथ बेहतर क्रियान्वयन के कारण आज बिहार में 180 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। कजरा (लखीसराय) में 301 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण कराया जा रहा है। इस परियोजना के साथ 495 मेगावाट आवर क्षमता की बैटरी स्टोरेज प्रणाली लगायी जा रही है जो देश की सबसे बड़ी बैटरी स्टोरेज की परियोजना है। राज्य में 4,945 मेगावाट की हरित ऊर्जा परियोजनाओं का एकरारनामा किया गया है।

पटना के विक्रम में नहर के किनारे 2 मेगावाट की सोलर परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ है। दरभंगा एवं सुपौल में फ्लोटिंग सोलर परियोजना का निर्माण किया गया है। फुलवरिया (रजौली) में भी एक फ्लोटिंग सोलर परियोजना पर कार्य किया जा रहा है।

किसान बन रहे सशक्त

राज्य सरकार ने फीडर सोलराइजेशन के तहत पीएम कुसुम योजना को ग्रामीण सशक्तिकरण का स्तंभ बनाया है।

इसके तहत 3,681 कृषि फीडर सोलर से जोड़े जाने का लक्ष्य है। किसान अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर आय अर्जित कर सकेंगे। यह योजना सौर ऊर्जा को एक आर्थिक अवसर में भी बदलेगा।

हर छत बन रहा है बिजलीघर

घरों की छतों से ऊर्जा का संचार हो रहा है। ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप सोलर परियोजना के तहत अब तक 11,383 सरकारी भवनों की छतों पर 100 मेगावाट क्षमता के सौर पावर प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। इसी योजना के अंतर्गत 5,683 निजी घरों में भी 21 मेगावाट के सौर पैनल लगाए जा चुके हैं, जिससे आम नागरिक भी ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं।

गांव की गलियों में रोशनी की नई कहानी

मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना राज्य की एक महत्त्वाकांक्षी योजना है जो गांव-गांव रोशनी पहुंचा रही है। अब तक 5 लाख 50 हजार से अधिक सोलर स्ट्रीट

लाइट्स स्थापित किये जा चुके हैं, जिनका सीधा लाभ ग्रामीण जनता को मिल रहा है। यह केवल रोशनी नहीं, बल्कि सुरक्षा, सुविधा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी बड़ा कदम है।

यह बदलाव सिर्फ राज्य सरकार का प्रयास नहीं है, यह हर उस नागरिक का योगदान भी है जिसने सौर ऊर्जा को अपनाया, अपनी छत पर पैनल लगवाया, अपने गांव में स्ट्रीट लाइट का स्वागत किया। यह कहानी उस बिहार की है जो अब अपने भविष्य की दिशा खुद तय कर रहा है।

बैटरी ऊर्जा भण्डारण प्रणाली में बिहार अग्रणी राज्य!

ऊर्जा भंडारण के विकास में बिहार ने महत्वपूर्ण पहल की है। राज्य में 2,500 मेगावाट आवर ऊर्जा भंडारण प्रणाली को विकसित किया जा रहा है। इसमें 500 मेगावाट आवर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को विकसित करने से संबंधित निविदा प्रक्रियाधीन है।

बिहार में इससे पहले लखीसराय के कजरा में 301 मेगावाट की दो बड़ी सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं के साथ कुल 495 मेगावाट आवर क्षमता की देश की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के विकास पर कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।

राज्य में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजना के निर्माण से राज्य में बढ़ती बिजली की मांग विशेषकर पीक आवर के दौरान मांग को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

राज्य में तेजी से बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करते हुए लोगों को सस्ती बिजली मुहैया कराने की दिशा में ऊर्जा विभाग ने विद्युत भंडारण प्रणाली के विकास के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की यह पहल राज्य सरकार की दूरदर्शी सोच का प्रतिफल है जिसके माध्यम से आज राज्य के लोगों को न केवल सूर्यास्त के बाद भी निर्बाध बिजली उपलब्ध करायी जाएगी, बल्कि उन्हें सस्ती बिजली देकर आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में सफलता मिलेगी। राज्य सरकार ने बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के विकास की महत्ता को उच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य के ग्रिड उपकेन्द्रों की जमीन पर 500 मेगावाट आवर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की परियोजना को स्वीकृति दी है, जिसके उपरांत इसके कार्यान्वयन एजेन्सी के चयन के लिए निविदा भी निकाल दी गई है।

यह परियोजना टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से कार्यान्वित कराई जाएगी। इस प्रक्रिया से परियोजना कार्यान्वयन से न केवल भंडारित बिजली का दर काफी सस्ता होगा बल्कि, परियोजना निर्माण कार्य भी अत्यंत कम समय में पूर्ण किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना के निर्माण में राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी नहीं आयेगा।

इस परियोजना के लिए कुल लागत का अधिकतम 30 प्रतिशत अथवा 27 लाख रुपये प्रति मेगावाट आवर केन्द्र सरकार के स्तर से Viability Gap Funding Scheme के स्तर से उपलब्ध कराया जाएगा। शेष 70 फीसदी राशि का वहन भंडारण प्रणाली

विकासकर्ता एजेंसी के स्तर से किया जाएगा। इस परियोजना को स्थापित करने के पहले चरण में राज्य के कुल चिन्हित 16 ग्रिड उपकेन्द्रों में उपलब्ध खाली जमीन पर किया जाएगा, ताकि भंडारित बिजली का दर अधिक नहीं हो।

उल्लेखनीय है कि पीक आवर के दौरान बिजली खरीदने की कीमत काफी अधिक होती है, जिसके कारण विद्युत वितरण कंपनियों को महंगे दर पर बिजली उपलब्ध कराना पड़ता है। इस कारण इस परियोजना से न सिर्फ पीक आवर में सूर्यास्त के बाद भी बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, बल्कि उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली भी मिलेगी। इस परियोजना से नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्रय के लिए निर्धारित मात्रा के लक्ष्य (Renewable Purchase Obligation) की पूर्ति करने में सफलता मिलेगी।

गौरतलब है कि बिहार में सौर ऊर्जा की उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर नई परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। अबतक राज्य में 1920 मेगावाट सौर ऊर्जा उपलब्धता पर कार्य प्रारंभ है। ऐसे में इस परियोजना के तहत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का विकास न केवल राज्य के लोगों को बिजली उपलब्ध में सुविधा होगी, बल्कि वितरण कंपनियों को भी वित्तीय लाभ होगा।

राज्य में बिजली से हो रही नई कृषि क्रांति

बिहार में बिजली से आई कृषि क्रांति ने किसानों को आत्मनिर्भर बना दिया है। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत किसानों को मिल रहे मुफ्त बिजली कनेक्शन, उन्हें नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर रही हैं। सस्ती बिजली, समर्पित कृषि फीडर और फीडर सोलराइजेशन जैसी पहलों से कृषि को अधिक लाभकारी बनाया जा रहा है। यह परिवर्तन न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति सुधार रहा है, बल्कि बिहार को कृषि क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा है।

बिहार के किसान आज आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। अपनी फसलों को लेकर वे पूर्व की तरह चिंतित नहीं रहते। उन्हें पता है कि मॉनसून का साथ न देने के बावजूद उनकी फसलों को नुकसान नहीं होगा क्योंकि उनके खेतों में पानी पहुंचाने के लिए राज्य सरकार सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध है। कृषि कार्य के लिए बिजली की उपलब्धता को लेकर किसानों में व्याप्त यही विश्वास बिहार में कृषि क्रांति की आधारशिला बन गई है।

बिहार में कृषि धीरे धीरे बिजली पर आधारित होती जा रही है। पहले किसान सिंचाई के लिए मुख्य रूप से डीजल पंपों पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब बिजली से चलने वाले पंपों की सहायता से वे कम लागत में अपनी फसलों की सिंचाई कर पा रहे हैं। इससे उनकी आय में भी वृद्धि हो रही है और खेती करना पहले की तुलना में अधिक आसान हो गया है।

मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना

मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना ने बिहार में कृषि क्षेत्र को नई दिशा दी है। इस योजना के तहत किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किया जा रहा है, जिससे वे कम लागत में सिंचाई कर सकते हैं। अभी तक राज्य के 5 लाख से अधिक किसानों को कृषि विद्युत संबंध दिया जा चुका है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत किसानों को मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट बिजली दी जा रही है, जिससे उनकी खेती की लागत काफी हद तक कम हो गई है। अब बिजली से पटवन करना डीजल से दस गुणा से अधिक सस्ता है।

पहले जब सही समय पर मॉनसून नहीं आता था, तो किसानों की परेशानी बढ़ जाती थी। उन्हें बीज बोने और फसल की सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर रहना पड़ता था या फिर महंगे डीजल पंप का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन अब किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध होने से वे पूरे साल सिंचाई कर पा रहे हैं और उनकी पैदावार भी बढ़ रही है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया को भी बहुत सरल बनाया गया है। किसान बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वे बिजली विभाग के 'सुविधा' ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बिजली वितरण कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।

इसके अलावा, जो किसान ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, वे बिजली विभाग के नजदीकी कार्यालयों में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को सरल और सहज बनाकर यह सुनिश्चित किया गया है कि हर किसान को इस योजना का लाभ मिल सके।

डेडिकेटेड कृषि फीडर

राज्य सरकार ने किसानों के लिए समर्पित कृषि फीडर (Dedicated Agriculture Feeder) तैयार किए हैं, जिससे उन्हें निर्बाध बिजली आपूर्ति की जा रही है। पहले गांवों में घरेलू और कृषि उपयोग के लिए एक ही ग्रिड से बिजली दी जाती थी, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए

समय पर बिजली नहीं मिल पाती थी। अब इन समर्पित कृषि फीडरों के माध्यम से किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। इससे किसानों को तय समय पर बिजली मिल रही है और वे अपनी फसलों की बेहतर तरीके से देखभाल कर पा रहे हैं।

पूर्व की योजनाओं एवं वर्तमान RDSS योजना के तहत कुल 2200 से अधिक डेडिकेटेड कृषि फीडर का निर्माण किया जा चुका है।

फीडर सोलराइजेशन

बिहार सरकार ने फीडर सोलराइजेशन की दिशा में भी तेजी से कदम बढ़ाए हैं। इस पहल के तहत सौर ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पादन किया जा रहा है, जिससे किसानों को सस्ती और स्थायी बिजली मिल सके। इससे बिजली उत्पादन की लागत कम होगी और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा।

बिजली की सुविधा बढ़ने से किसानों की आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब वे वर्षभर फसलों की सिंचाई कर सकते हैं, जिससे वे एक साल में अधिक बार फसल उगा पा रहे हैं।

फीडर सोलराईजेशन (पीएम कुसुम योजना) के तहत राज्य में 3681 कृषि/मिश्रित फीडरों के सोलराईजेशन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत इच्छुक किसानों को ₹1.05 करोड़ केन्द्रीय अनुदान तथा ₹45 लाख राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है।

बिहार सरकार की इन पहलों ने राज्य को कृषि के लिए एक नए मॉडल के रूप में स्थापित कर दिया है। अन्य राज्यों में भी बिहार की इस नीति को अपनाने की चर्चा हो रही है।

बिहार में बिजली से आई कृषि क्रांति ने न केवल किसानों को आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि कृषि क्षेत्र में स्थायी विकास की नींव भी रखी है। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना, डेडिकेटेड कृषि फीडर और फीडर सोलराइजेशन जैसी पहलों ने किसानों की जिंदगी को आसान बना दिया है।

बिहार की यह बिजली आधारित कृषि क्रांति दिखाती है कि सही नीतियों और योजनाओं के साथ किसानों को कैसे राज्य के विकास यात्रा में शामिल किया जा सकता है। यह बदलाव सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे बिहार के आर्थिक और सामाजिक विकास में भी अहम योगदान दे रहा है।

राज्य में 'पीएम सूर्य घर योजना' के लिए विशेष पहल

बिहार के जमुई जिले में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा एक स्टॉल लगाया गया, जहां माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को राज्य में संचालित पीएम सूर्य घर योजना का डेमो मॉडल प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री महेंद्र कुमार की उपस्थिति में उनकी टीम ने कई सौर ऊर्जा संबंधी परियोजनाओं को प्रस्तुत किया।

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड की टीम ने माननीय प्रधानमंत्री एवं अन्य गणमान्य अतिथियों के समक्ष अन्य मॉडल मिनी ग्रिड भी प्रदर्शित किए। इनमें एक विशेष मॉडल मिनी ग्रिड सोलर सिस्टम था, जो छोटे और मध्यम स्तर के समुदायों के लिए सौर ऊर्जा आधारित विद्युत आपूर्ति का एक प्रभावी समाधान प्रस्तुत करता है। इस मॉडल के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध कराना संभव होगा जहाँ अब तक विद्युत आपूर्ति सीमित या अनुपलब्ध रही है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने स्टैंड अलोन सोलर प्लांट की अवधारणा भी प्रस्तुत की, जो दूरदराज के गांवों में ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने का एक सशक्त माध्यम बन सकता है। इन प्रयासों से बिजली से वंचित क्षेत्रों को रोशन किया जा सकेगा और आत्मनिर्भर बिहार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एनबीपीडीसीएल एवं एसबीपीडीसीएल को प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति मिली

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (NBPDCL) और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (SBPDCL) को वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2023–24 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा क्रमशः ₹14.48 करोड़ एवं ₹4.67 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है।

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के लाभार्थियों ने गणतंत्र दिवस परेड 2025 में बिहार का बढ़ाया मान

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत चयनित बिहार के 33 लाभार्थियों को गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर कर्तव्य पथ, नई दिल्ली में आयोजित परेड में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।

अरवल, गया, पटना, भागलपुर, नवादा सहित राज्य के विभिन्न जिलों से चयनित इन लाभार्थियों ने अपने घरों की छतों पर सौर पैनल स्थापित कर ''शून्य बिजली बिल'' प्राप्त किए हैं, जिससे वे इस योजना के प्रेरणास्रोत बने हैं।

यह उपलब्धि बिहार में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है और सौर ऊर्जा अपनाने में राज्य की प्रतिबद्धता को राष्ट्रीय मंच पर दर्शाती है। इस योजना के तहत निजी घरों के छतों पर सोलर संयंत्र लगाने के लिए सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को अनुदान भी दिया जा रहा है।

पीरपैंती में 2400 मेगावाट
ताप विद्युत परियोजना की शुरूआत

बिहार के पीरपैंती (भागलपुर) में 3X800 मेगावाट (कुल 2400 मेगावाट) ताप विद्युत परियोजना की स्थापना को मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। यह परियोजना टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी टेंडर (टीबीसीबी) के तहत क्रियान्वित की जाएगी और इसकी नोडल एजेंसी बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड होगी। इस परियोजना से राज्य की ऊर्जा उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और यह बिहार को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पहले इस स्थल पर सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना थी, लेकिन विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा किए गए विस्तृत अध्ययन में पाया गया कि पीरपैंती का भू-भाग सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। वहीं, इस भूमि पर ताप विद्युत परियोजना की संभावनाओं को बेहतर पाया गया, क्योंकि यह कोयला स्रोतों के पास स्थित है, जिससे परिवहन लागत में कमी आएगी और ऊर्जा उत्पादन अधिक किफायती होगा।

पीरपैंती में ताप विद्युत परियोजना की स्थापना से राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह परियोजना न केवल राज्य के औद्योगिक विकास को गति देगी, बल्कि बिहार को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित होगी, जिससे पर्यावरणीय प्रभावों को कम करते हुए अधिकतम ऊर्जा उत्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही, इस परियोजना के लिए टैरिफ आधारित निविदा अपनाई जाएगी, जिससे परियोजना का निर्माण न केवल ससमय होगा बल्कि राज्य के लोगों को उचित दर पर बिजली भी मिलेगी।

इस परियोजना से राज्य के ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी जिससे राज्य की बिजली जरूरतें पूरी होंगी। परियोजना स्थल ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के कोयला खदानों के नजदीक है, जिससे उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिलेगी। इसके अलावा इस परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी सृजित होंगे। यह परियोजना राज्य में निजी निवेश की सबसे बड़ी परियोजना होगी।

ऊर्जा सचिव ने पीरपैंती में ऊर्जा ताप घर की जमीन का किया निरीक्षण

प्रतिनिधि, पीरपैंती

बिहार सरकार के ऊर्जा सचिव पंकज पाल ने रविवार को पीरपैंती पहुंच 21,400 करोड़ की लागत से बनने वाले 2400 मेगा वाट के थर्मल पावर प्लांट का स्थल निरीक्षण किया. निरीक्षण में विद्युत अधीक्षण अभियंता रितु अभिषेक, ऊर्जा विभाग के अधिकारी, अनुमंडलीय स्तर के अधिकारी, जेई शुभम कुमार, बीपीआरओ, पीरपैंती थानाध्यक्ष नीरज कुमार पुलिस जवानों के साथ चौक-चौराहा पर मुस्तैदी से डटे रहे. ऊर्जा सचिव जमीन कहां व किस परिस्थिति में है, बाउंड्री सहित अन्य कार्यों से अवगत हुए ,उन्होंने बाउंड्री के चारों तरफ का भौतिक निरीक्षण किया. पीरपैंती के टुंडवा मुंडवा मौजा से मुरली पहाड़ सहित आसपास की विभिन्न ऊंचाई वाले जगहों का निरीक्षण किया. उन्होंने कई मुख्य बातों से अवगत होकर तकनीकी संभावित प्रतिवेदन तैयार करने की बात कही. उन्होंने दानापुर पहाड़ के पीछे की जमीन अधिकृत करने को लेकर भौतिक निरीक्षण किया. उन्होंने मीडिया को बताया कि थर्मल पावर प्लांट प्रारंभिक स्थिति में है, हमलोग अभी स्थल भ्रमण कर रहे है. आगे की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. भूमि अधिग्रहण में विसंगतियों को लेकर कहा कि किसानों की समस्या सक्षम पदाधिकारी के द्वारा सुना जायेगा व समझा जाएगा जो नियम संभव होगा इसपर कार्रवाई की जायेगी.

उन्होंने कहा कि जितने जमीन अधिकृत की गयी है, उक्त जमीन पर जल्द से जल्द बाउंड्री का कार्य पूरा किया जायेगा. फिलहाल तकनीकी संभावित प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा, उसके आधार पर कितने मेगावाट का प्लांट लगेगा, किस प्रकार लगेगा वह सब टेक्निकली रिपोर्ट में बताया जायेगा.

डीपीआर बनने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी. किसान चेतना व उत्थान समिति के अध्यक्ष श्रवण सिंह ने ऊर्जा सचिव को आवेदन देकर प्रस्तावित ताप बिजली घर के लिए भू-अधिग्रहण के मुआवजा वितरण में धांधली की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की. मुखिया अरविंद साह ने बाढ़ के पानी को लेकर विस्तृत जानकारी दी. मुखिया को आश्वासन मिला कि जल्द ऊर्जा ताप घर का निर्माण शुरू होगा.

थर्मल पावर प्लांट का स्थल निरीक्षण करने जाते ऊर्जा सचिव पंकज पाल व अन्य.

पावर प्लांट की जमीन की घेराबंदी का काम जल्द होगा

पीरपैंती में ऊर्जा सचिव ने अधिकारियों के साथ पावर प्लांट के लिए अधिग्रहित जमीन का किया निरीक्षण

भास्कर न्यूज़ | पीरपैंती

पीरपैंती में 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट के लिए अधिग्रहीत जमीन का निरीक्षण रविवार को बिहार सरकार के ऊर्जा सचिव पंकज कुमार पाल, पावर जेनरेशन कंपनी के एमडी अवधेश सिंह सहित अधिकारियों ने की।

प्रखंड कार्यालय रोड के पास मुख्य गेट से पावर प्लांट की अधिगृहित जमीन पर नक्शा से पूरी भौगोलिक स्थिति को जाना। इसके बाद चारों ओर अधूरी पड़ी चहारदीवारी को भी देखा। करीब तीन घंटे से अधिक समय पैदल चलकर पूरे पांचों मौजा की जमीन का जायजा लिया। दानापुर पहाड़ से संधीय नाला के समीप गए, जहां से बाढ़ का पानी पावर प्लांट की अधिगृहित जमीन पर प्रवेश करता है। किस-किस मौजा में बाढ़ का पानी प्रवेश करता है। कितने दिनों तक पानी जमा रहता है, इसकी जानकारी ली। झारखंड से कोयला आपूर्ति का मार्ग और रानी दियारा, एकचारी दियारा के बीच गंगा से पानी की आपूर्ति की जानकारी ली। ऊर्जा सचिव ने बताया कि थर्मल पावर प्लांट की जमीन का निरीक्षण किया गया। जमीन कहीं ऊंची तो कहीं नीची है। किसानों की समस्या को सक्षम प्राधिकार के समक्ष सुना जाएगा। तकनीकी संविदा प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। इसके बाद कार्य में तेजी आएगी। जल्द ही अधूरी चार दिवारी निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। थर्मल पावर प्लांट के लिए वर्ष 2010-2011 में जमीन का अधिग्रहण किया गया था। 700 किसानों को मुआवजे का भुगतान हुआ है। ढाई किमी. तक चहारदीवारी निर्माण किया गया है। जबकि एक किलोमीटर में निर्माण कार्य अधूरा है। 800 मीटर ग्रेड बीम तक का कार्य हुआ है। किसानों की 988 एकड़, बिहार सरकारी की 112 एकड़ और रेलवे की 57 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। मौके पर विद्युत अधीक्षण अभियंता ऋतु अभिषेक, कार्यपालक अभियंता प्रभात रंजन, बीपीआरओ कामेश्वर नारायण, सहायक अभियंता शशिकांत, अभियंता ब्रजेश कुमार, दीपक चौधरी, शुभम कुमार आदि मौजूद थे।

पीरपैंती पावर प्लांट की जमीन के निरीक्षण के बाद नक्शा देखते ऊर्जा सचिव।

किसानों ने समस्या के समाधान को सौंपा ज्ञापन

थर्मल पावर प्लांट में जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है, भूअर्जन विभाग द्वारा भूमि विसंगति की समस्या है। किसान उत्थान चेतना समिति के अध्यक्ष श्रवण सिंह के नेतृत्व में किसानों ने सचिव को ज्ञापन सौंपा। श्रवण सिंह ने कहा कि 919 किसानों की जमीन पर हजारों आम सहित अन्य पेड़ हैं। पेड़ को झाड़ी दिखा कर मुआवजे का भुगतान किया गया। एक ही खाता का अलग-अलग खेसरा का दर निर्धारण किया गया है। स्थानीय अधिकारी बचने के लिए केंद्र व राज्य के अधिकारियों को गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। किसानों की समस्या समाधान के बाद ही प्रोजेक्ट लगे। उच्च स्तरीय जांच में जमीन के अधिग्रहण में गड़बड़ी का मामला स्पष्ट हो जाएगा। किसानों ने समस्या के समाधान के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

विद्युत राजस्व संग्रहण में बना नया कीर्तिमान

राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2024–25 में 17,114 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व संग्रह किया है । बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की अनुषंगी दोनों वितरण कंपनियों ने पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 2,005 करोड़ (13.27 प्रतिशत) अधिक राजस्व की वसूली कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वितरण कंपनियों द्वारा कुल संग्रहित राजस्व 17,114 करोड़ रुपए में से एनबीपीडीसीएल ने 7,937 करोड़ एवं एसबीपीडीसीएल ने 9,177 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। वितरण कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल 1900 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 49.37 प्रतिशत अधिक है।

राज्य की जनता और ऊर्जा विभाग के बीच परस्पर सामंजस्य, कंपनियों द्वारा प्रदत्त बेहतर सेवाओं तथा 24X7 बिजली आपूर्ति की उपलब्धता का ही परिणाम है कि उपभोक्ताओं ने अपने बिजली बिल का नियमित भुगतान किया है। इन सब की वजह से वितरण कंपनियों ने रिकॉर्ड राजस्व संग्रहण किया है। बेहतर उपभोक्ता सेवा, उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं लोगों के साथ सीधा संवाद ने भी राजस्व संग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

वितरण कम्पनियों के कार्यों को आंकने के लिए बिलिंग एवं कलेक्शन क्षमता देखी जाती है। बिलिंग तथा कलेक्शन क्षमता वृद्धि की बदौलत ही राज्य के उपभोक्ताओं को पिछले वर्षों से बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय भार के निरंतर सेवा प्रदान करने में वितरण कम्पनियां सफल रही हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 के बेहतर राजस्व संग्रहण के कारण वित्तीय वर्ष 2024–25 में सभी उपभोक्ताओं को विद्युत दर में 15 पैसे प्रति यूनिट की कमी का लाभ भी प्राप्त हुआ था। इस वर्ष भी और बेहतर राजस्व संग्रहण के कारण ग्रामीण क्षेत्र के 50 यूनिट से अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 54 पैसे प्रति यूनिट का लाभ मिलेगा जिससे राज्य के 1.28 करोड़ घरेलु ग्रामीण उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। साथ ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट कम दर पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।

वितरण कंपनियों द्वारा अपने एटी एंड सी लॉस को कम करने तथा आरडीएसएस के तहत की गई लॉस रिडक्शन की परियोजनाओं को ससमय पूर्ण करने का भी इस रिकॉर्ड राजस्व संग्रहण में उल्लेखनीय योगदान है। साथ ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

बिजली वितरण कम्पनियों की ए टी एंड सी लॉस राष्ट्रीय औसत से भी नीचे

बिहार की बिजली वितरण कम्पनियों ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2024–25 में समेकित तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि (ए टी एंड सी लॉस) को घटाकर 15.50 प्रतिशत कर दिया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2023–24 में 19.94 प्रतिशत थी। यह पहली बार है जब बिहार की एटीएंडसी लॉस भारत के सभी डिस्कॉम के राष्ट्रीय औसत 17.60 प्रतिशत से भी कम रही है। यह परिचालन प्रदर्शन में एक नया मील का पत्थर है। एनबीपीडीसीएल ने जहां अनुमानित एटी एंड सी लॉस को 14.5 प्रतिशत तक लाने में सफलता पाई है, वहीं एसबीपीडीसीएल ने इसे 17 प्रतिशत तक घटाया है, जो दोनों वितरण कंपनियों की प्रतिबद्धता और दक्षता को दर्शाता है।

यह उपलब्धि अनेक रणनीतिक प्रयासों और सुधारों का परिणाम है। वितरण प्रणाली की विश्वसनीयता में सुधार, समयबद्ध रूप से नए कनेक्शन प्रदान करना, सटीक और पारदर्शी बिलिंग पर ज़ोर देना, तथा उपभोक्ता विश्वास हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली की प्रभावशीलता और उपभोक्ताओं के साथ संवाद बढ़ाने के प्रयासों ने भी इस उपभोक्ता–केंद्रित दृष्टिकोण को मज़बूती प्रदान की है। इन सभी पहलों ने ज़मीनी स्तर पर उत्तरदायित्व और प्रदर्शन में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

एटी एंड सी लॉस में कमी के कारण राजकोष के वित्तीय बोझ में कमी आई

राज्य की वितरण कंपनियों द्वारा किए गए उल्लेखनीय सुधार और बेहतर प्रबंधन के कारण वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 से एग्रीगेट टेक्निकल एवं कमर्शियल लॉस (AT&C Loss) के मद में सरकारी अनुदान की आवश्यकता समाप्त हो गई है। इससे राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों पर पड़ने वाला भार कम हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2022–23 के दौरान वितरण कंपनियों को क्रमशः 860 करोड़, 1266 करोड़, 1422 करोड़ एवं 1094 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में प्राप्त हुए थे। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में वितरण कंपनियों ने एटी एंड सी लॉस को लगातार कम किया है और राजस्व संग्रहण में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है। इन सुधारों के परिणामस्वरूप वितरण कंपनियों को इस अनुदान की आवश्यकता नहीं रही, जिससे राज्य सरकार के कोष पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ा।

ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे इन सकारात्मक परिवर्तनों के कारण राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण में वितरण कंपनियों का योगदान निरंतर बढ़ रहा है। इन कंपनियों के बेहतर वित्तीय प्रदर्शन से राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति और अधिक सशक्त होगी, जिससे बुनियादी ढांचे के विकास, सामाजिक कल्याण और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

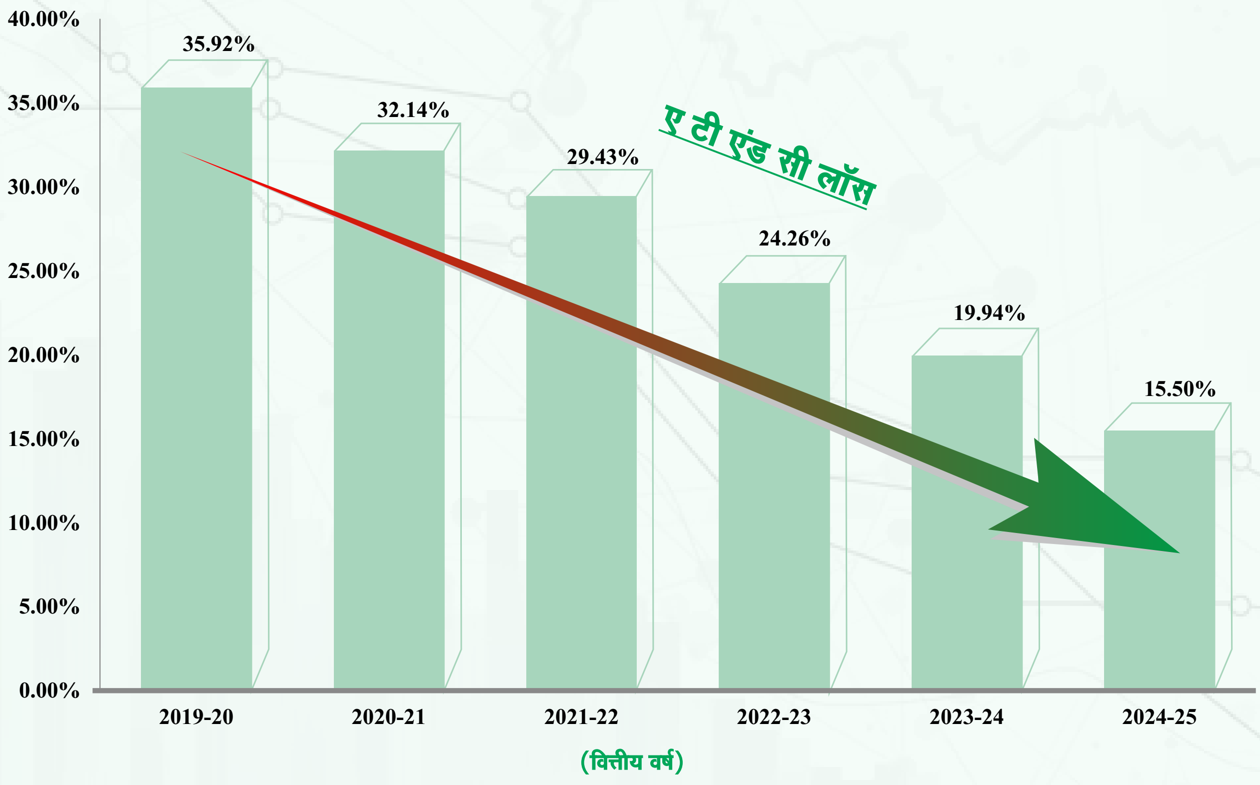

ऊर्जा प्रक्षेत्र में सम्मानों से गौरवान्वित बिहार

स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बेहतर क्रियान्वयन के लिए बीएसपीएचसीएल को ईटी गवर्मेंट डिजिटेक अवॉर्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार

बिहार को स्मार्ट प्रीपेड मीटर तकनीक के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 'द इकोनॉमिक टाइम्स' द्वारा नई दिल्ली में आयोजित **ईटी गवर्मेंट डिजिटेक अवार्ड 2025** में स्वर्ण पुरस्कार से नवाज़ा गया।

राज्य की विशेष पहल, 'बिहार् प्राऊड टॉर्च बियरर ऑफ यूनिवर्सल स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग फॉर दी नेशन' को जूरी द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लीडर इन पब्लिक सेक्टर में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह उपलब्धि राज्य के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि राज्य ने स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम की है। इस अवॉर्ड का ऊर्जा विभाग के सचिव सह सीएमडी बीएसपीएचसीएल श्री पंकज कुमार पाल ने ग्रहण किया।

स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग को राज्य भर में लागू करने का लक्ष्य उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, बिलिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और ऊर्जा प्रबंधन को अधिक कुशल बनाना था। इस पहल की सफलता के पीछे व्यापक प्रचार–प्रसार और जागरूकता अभियान की अहम भूमिका रही, जिसके तहत उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर के लाभों से अवगत कराया गया और उन्हें इसे अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। ग्रामीण इलाकों में चेक मीटर लगाए गए ताकि उपभोक्ता खुद आ कर जांच करें कि डिजिटल और स्मार्ट मीटर में कोई फर्क नहीं है। सभी सरकारी भवनों में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर अधिष्ठापित किए जा रहे हैं। साथ ही उपभोक्ताओं को पम्पलेट वितरण एवं मोबाइल वैन के जरिए जागरूक किया गया। स्कूल और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाया गया, जीविका दीदियों ने घर घर जा कर गांवों में लोगों को स्मार्ट मीटर की विशेषताओं से अवगत कराया। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से एवं मेले में स्टाल लगा कर लोगों को स्मार्ट मीटर के फायदों के बारे में बताया गया। समय समय पर उन्हें साइबर फ्रॉड से बचने के उपायों से भी अवगत कराया गया।

वितरण कंपनियों ने विभिन्न माध्यमों जैसे जन जागरूकता कार्यक्रमों, डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्थानीय शिविरों, नुक्कड़ नाटक, सोशल मीडिया और उपभोक्ता संवाद अभियानों के माध्यम से लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर बिजली उपभोक्ताओं को गलत बिलिंग से मुक्ति दिलाने, ऊर्जा की बचत करने और अपने खर्च पर नियंत्रण रखने में सहायक होगा। इन प्रयासों का ही नतीजा है कि आज बिहार स्मार्ट मीटरिंग को अपनाने में पूरे देश का नेतृत्व कर रहा है।

गया जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना की शुरुआत हुई थी, ताकि उपभोक्ताओं को गलत बिलिंग की समस्या से राहत मिल सके और बिजली बिल का पारदर्शी रिकॉर्ड रखा जा सके। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता को देखते हुए इसे पूरे राज्य में लागू किया गया, जिससे लाखों उपभोक्ताओं को लाभ मिल रहा है।

राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की सफलता को समझने के लिए अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों ने बिहार का दौरा किया एवं उपभोक्ताओं व अभियंताओं से संवाद किया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा समय समय पर स्मार्ट मीटर की सफलता के लिए बिहार की प्रशंसा होती रही है।

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 – एनबीपीडीसीएल की ऐतिहासिक उपलब्धि

ऊर्जा संरक्षण और दक्षता बढ़ाने की दिशा में बिहार ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एनबीपीडीसीएल) को डिस्कॉम श्रेणी में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (एनईसीए) 2024 का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार 14 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में एनबीपीडीसीएल के प्रबंध निदेशक डॉ. निलेश रामचंद्र देवरे ने प्राप्त किया।

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) द्वारा प्रदान किया जाता है। यह उन संगठनों को दिया जाता है जो ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। एनबीपीडीसीएल ने इस पुरस्कार के लिए विभिन्न मानकों पर सर्वोच्च अंक प्राप्त किए, जिनमें शामिल हैं:

- ✶ एटी एंड सी लॉस (AT&C Loss) में कमी
- ✶ उन्नत वितरण प्रणाली का निर्माण
- ✶ स्मार्ट प्रीपेड मीटर का बड़े पैमाने पर उपयोग
- ✶ मीटर्ड एग्रीकल्चर उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि

ऊर्जा दक्षता में सुधार

इन सभी मापदंडों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर एनबीपीडीसीएल ने ऊर्जा दक्षता और स्थिरता के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है।

बिहार में ऊर्जा सुधार और भविष्य की योजनाएं

एनबीपीडीसीएल की इस सफलता के पीछे ऊर्जा क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किए गए विभिन्न सुधार और नवाचार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें शामिल हैं:

1. **सौर ऊर्जा को बढ़ावा :** सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं ताकि पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम हो।
2. **फीडर सोलराइजेशन योजना :** किसानों को खेतों में सोलर पैनल लगाने की सुविधा दी जा रही है, जिससे वे बिजली उत्पादन और खेती दोनों कर सकें।
3. **ग्रिड–कनेक्टेड रूफटॉप सोलर योजना :** नागरिकों को अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे उनके बिजली बिल में कटौती हो सके।

एनबीपीडीसीएल को उपभोक्ता सेवा रेटिंग में ए-ग्रेड प्राप्त

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम कंज्यूमर सर्विस रेटिंग 2023–24 में ए ग्रेड प्राप्त हुआ है। यह ग्रेडिंग उपभोक्ताओं को उत्कृष्ट और निर्बाध बिजली सेवा प्रदान करने की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

एनबीपीडीसीएल को यह रेटिंग ऑपरेशनल रिलायबिलिटी, कनेक्शन और अन्य सेवाओं, मीटरिंग–बिलिंग और कलेक्शन, तथा फॉल्ट सुधार और शिकायत निवारण जैसे चार प्रमुख मानकों पर प्रदर्शन के आधार पर दी गई है।

पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की वर्गीकरण सूची में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को मिली A+ की शीर्ष रैंकिंग

भारत सरकार के उपक्रम पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य विद्युत संस्थाओं की वर्गीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (बीएसपीटीसीएल) को वर्गीकरण में A+ की शीर्ष रैंकिंग मिली है। बीएसपीटीसीएल अपनी उत्कृष्ट कार्यक्षमता का प्रदर्शन करते हुए वित्तीय सुदृढ़ता, ससमय परियोजनाओं का कार्यान्वयन, सक्षम परिचालन एवं अनुरक्षण के मापदंड पर शानदार काम कर रही है।

बिहार में विद्युत आधारभूत संरचनाओं के विकास के क्षेत्र में निरंतर कार्य हो रहा है। पावर ट्रांसमिशन की जिम्मेदारी बीएसपीटीसीएल कुशलतापूर्वक निभा रही है। यह गर्व की बात है कि बीएसपीटीसीएल अपने कार्य की बदौलत पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किए गए राज्य विद्युत संस्थाओं के वर्गीकरण में A+ की शीर्ष रैंकिंग मिली है।

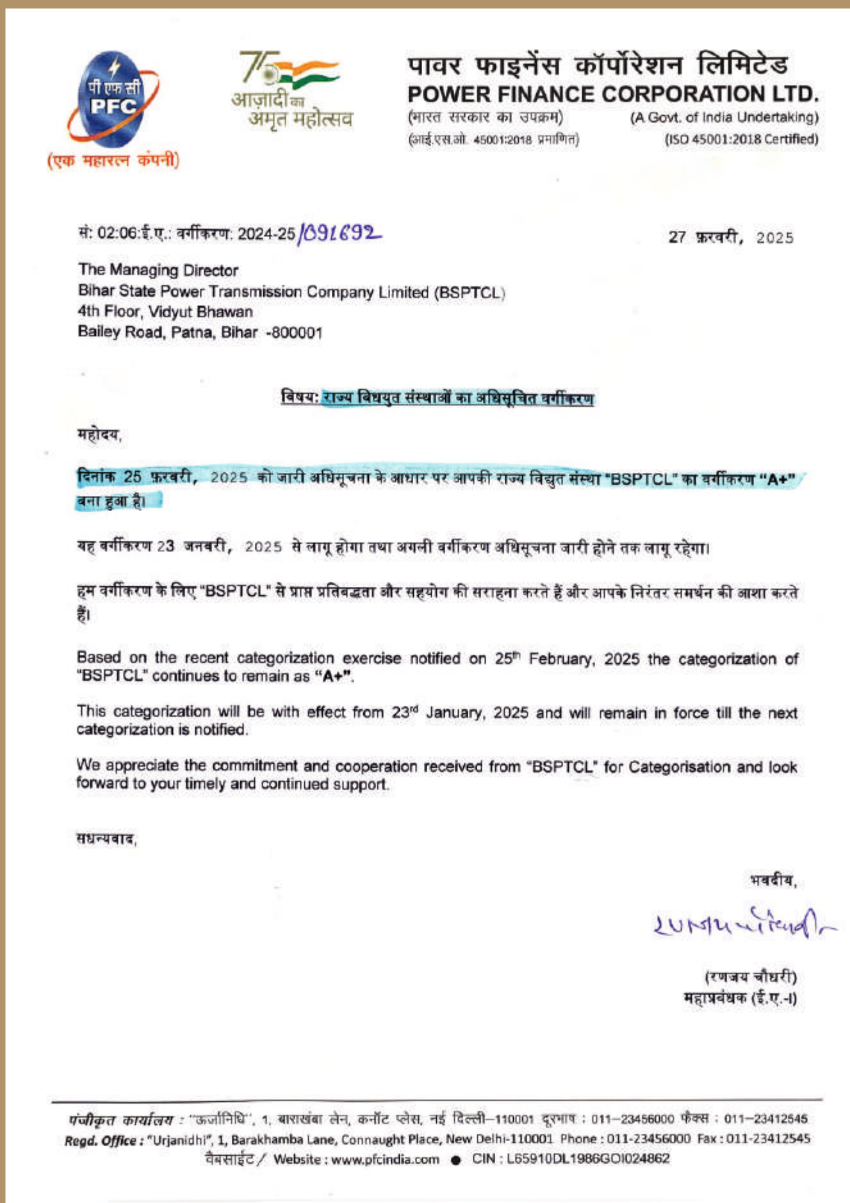

(एक महारत्न कंपनी)

आज़ादी का अमृत महोत्सव

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
POWER FINANCE CORPORATION LTD.
(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)
(आई.एस.ओ. 45001:2018 प्रमाणित) (ISO 45001:2018 Certified)

सं: 02:06:ई.ए.: वर्गीकरण: 2024-25/091692 — 27 फ़रवरी, 2025

The Managing Director
Bihar State Power Transmission Company Limited (BSPTCL)
4th Floor, Vidyut Bhawan
Bailey Road, Patna, Bihar -800001

विषय: राज्य विधयुत संस्थाओं का अधिसूचित वर्गीकरण

महोदय,

दिनांक 25 फ़रवरी, 2025 को जारी अधिसूचना के आधार पर आपकी राज्य विद्युत संस्था "BSPTCL" का वर्गीकरण "A+" बना हुआ है।

यह वर्गीकरण 23 जनवरी, 2025 से लागू होगा तथा अगली वर्गीकरण अधिसूचना जारी होने तक लागू रहेगा।

हम वर्गीकरण के लिए "BSPTCL" से प्राप्त प्रतिबद्धता और सहयोग की सराहना करते हैं और आपके निरंतर समर्थन की आशा करते हैं।

Based on the recent categorization exercise notified on 25th February, 2025 the categorization of "BSPTCL" continues to remain as **"A+"**.

This categorization will be with effect from 23rd January, 2025 and will remain in force till the next categorization is notified.

We appreciate the commitment and cooperation received from "BSPTCL" for Categorisation and look forward to your timely and continued support.

सधन्यवाद,

भवदीय,

(रणजय चौधरी)
महाप्रबंधक (ई.ए.-I)

पंजीकृत कार्यालय : "ऊर्जानिधि", 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 दूरभाष : 011–23456000 फैक्स : 011–23412545
Regd. Office : "Urjanidhi", 1, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi-110001 Phone : 011-23456000 Fax : 011-23412545
वैबसाईट / Website : www.pfcindia.com ● CIN : L65910DL1986GOI024862

बिजली के बेहतर उपयोग के लिए एआई-संचालित विश्लेषण को अपनाने में बिहार अव्वल

''बिहार जो आज करता है, उसे पूरा देश कल अपनाता है।'' इस कहावत को बिहार ने एक बार फिर से सच कर दिखाया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने आरईसी लिमिटेड और एसआईएनई (SINE) आईआईटी मुंबई के सहयोग से पॉवरथॉन 2022 की शुरुआत की थी। ऊर्जा विभाग द्वारा बिहार की अनुशंसा के आधार पर ऊर्जा मंत्रालय ने कई संभावित राज्यों का मूल्यांकन करने के बाद बिहार को चुना।

जहां कई राज्य केवल पायलट चरण तक सीमित रहे, वहीं बिहार ने निर्णायक कदम उठाते हुए पॉवरथॉन 2022 के शीर्ष फाइनलिस्ट बिजली (बिजली टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड) के एआई–आधारित एनर्जी लीकेज डिटेक्शन समाधान को अपनाया। बिहार की इस तत्परता ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को अन्य राज्यों की तुलना में बिहार को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया, जिससे पूर्ण पैमाने पर उन्नत तकनीकी समाधान लागू किए जा सके।

उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने के लिए आधारभूत संरचना से लेकर वितरण तक को सुदृढ़ किया जा चुका है। अब वितरण व्यवस्था में और सुधार के साथ–साथ उपभोक्ताओं को बिजली की बचत करने हेतु प्रेरित करने के लिए एआई का भी इस्तेमाल किया जाएगा।

पॉवरथॉन 2022 एक राष्ट्रव्यापी पहल थी, जिसका उद्देश्य बिजली वितरण से जुड़ी जटिल चुनौतियों के लिए उन्नत तकनीकी समाधान खोजना और लागू करना था।

इस पहल के माध्यम से बिहार केवल राजस्व हानि को रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के ऊर्जा क्षेत्र को भविष्य की दिशा में अग्रसर करने में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इससे विश्वसनीय, कुशल और उपभोक्ता–केंद्रित ऊर्जा प्रबंधन सुनिश्चित होगा।

ऊर्जा विभाग द्वारा बिहार की अनुशंसा के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने कई संभावित राज्यों का मूल्यांकन करने के बाद बिहार को चुना क्योंकि स्मार्ट मीटर अपनाने में बिहार सबसे आगे था। यह एकमात्र राज्य था जिसने निर्भीकता के साथ पॉवरथॉन की अभिनव तकनीकों को अपनाया और स्मार्ट मीटर डेटा का उपयोग कर समस्याओं को हल करने के लाभों को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विद्युत प्रक्षेत्र में इस्तेमाल करने की दिशा में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने कदम बढ़ाते हुए आरईसी लिमिटेड और बिजली टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक करार भी किया है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को एआई संचालित उर्जा विश्लेषण प्रदान किए जाएंगे। डाटा–आधारित निर्णयों के माध्यम से अपने बिजली बिलों को कम करने में उन्हें सुविधा होगी। यह पहल केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के दिशा निर्देश पर शुरु की गई है।

राज्य में पहली बार हॉटलाइन मेंटेनेंस के अभिनव तकनीक का प्रयोग

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने राज्य में पहली बार हॉटलाइन मेंटेनेंस तकनीक का उपयोग करते हुए ग्रिड उपकेंद्रों और संचरण लाइनों की मरम्मत का कार्य शुरू किया है। इस अत्याधुनिक तकनीक का मुख्य लाभ यह है कि मरम्मत के दौरान विद्युत आपूर्ति को बंद करने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे उपभोक्ताओं को बिना किसी रुकावट के बिजली मिलती रहती है। इस पहल की शुरुआत पटना पश्चिमी अंचल के बिहटा–दीघा ग्रिड उपकेंद्र में की गई है और जल्द ही इसे राज्य के अन्य हिस्सों में भी लागू किया जाएगा।

इस तकनीक के उपयोग से बिजली उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति, मरम्मत कार्य में तेजी, और लागत में कमी जैसे महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे। पारंपरिक रखरखाव प्रक्रिया में, मरम्मत के दौरान ट्रांसमिशन लाइनों को बंद करना पड़ता था, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित होती थी। हॉटलाइन मेंटेनेंस के माध्यम से लाइन में विद्युत प्रवाह जारी रहते हुए विशेष सुरक्षा उपकरणों एवं इंसुलेटेड टूल्स की मदद से मरम्मत कार्य किया जाता है। इससे ब्लैकआउट की संभावना कम होती है एवं बिजली कटौती के कारण होने वाली असुविधा कम होती है ।

बीएसपीटीसीएल ने इस तकनीक को लागू करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित तकनीशियनों एवं इंजीनियरों की एक टीम गठित की है, जो आधुनिक इंसुलेटेड बूम ट्रक, ग्लव्स, हेलमेट और अन्य विशेष उपकरणों का उपयोग करके उच्च वोल्टेज लाइनों पर मरम्मत कार्य करने में सक्षम है। इस तकनीक में कार्यकर्ताओं को ''लाइन पर लाइव वर्किंग'' के लिए विशेष सुरक्षा उपायों के तहत प्रशिक्षित किया गया है, जिससे वे बिना बिजली काटे मरम्मत कर सकते हैं।

राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा लाभ

इस तकनीक के इस्तेमाल से बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को अधिक विश्वसनीय, स्थिर और सतत् बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। अब तक, मरम्मत कार्य के लिए बार–बार बिजली कटौती करनी पड़ती थी, जिससे घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को परेशानी होती थी। हॉटलाइन मेंटेनेंस तकनीक के लागू होने से यह समस्या दूर होगी, जिससे बिहार के आर्थिक और औद्योगिक विकास को भी बल मिलेगा।

ट्रांसमिशन कंपनी की योजना है कि इस तकनीक का विस्तार अन्य प्रमुख ग्रिड उपकेंद्रों और संचरण लाइनों तक किया जाए, जिससे पूरे राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इसके तहत कंपनी अपने कर्मचारियों को और अधिक विशेषीकृत प्रशिक्षण दे रही है और नवीनतम उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है।

स्व0 अमरेन्द्र कुमार झा
की स्मृति में समर्पित

श्रद्धा सुमन

ऊर्जा परिवार के सदस्य स्व0 अमरेन्द्र कुमार झा, लेखापाल, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, एक समर्पित एवं अनुशासित सदस्य होने के साथ–साथ एक उत्कृष्ट खिलाड़ी भी थे जिनकी 01 दिसम्बर 2024 को आयोजित मैराथन दौड़ के दौरान असामयिक मृत्यु हो गई। यह घटना पूरे ऊर्जा परिवार के लिए अत्यंत हीं दुखद है।

मुंगेर जिले के कुँआगढ़ी ग्राम में 9 जनवरी 1977 को जन्मे स्व0 अमरेन्द्र, स्व0 रत्नेश्वर प्रसाद झा के पुत्र थे, जिनकी नियुक्ति कनीय लेखा लिपिक के पद पर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, कंपनी मुख्यालय में हुई थी। वर्ष 2011 से पदस्थापित स्व0 झा की पहचान एक अच्छे लेखापाल के साथ एक बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में भी थी। जिनकी असामयिक निधन की खबर सुन बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक श्री पंकज कुमार पाल एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री महेन्द्र कुमार समेत सैकड़ों विद्युतकर्मियों ने बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के कॉलोनी में स्थित उनके आवास पर पहुँच कर दिवंगत आत्मा के प्रति शोक संवेदना व्यक्त किया। इस दूखद घड़ी में सभी ने उनकी पत्नी, पुत्री एवं पुत्र की हिम्मत बढ़ायी। उनके सम्मान में ऊर्जा टर्फ स्टेडियम में श्रद्धांजलि स्वरूप एक फुटबॉल मैच का भी आयोजन किया गया।

विद्युत कम्पनी एवं खेल के प्रति अमरेन्द्र कुमार झा के समर्पण भाव को ऊर्जा परिवार सदैव याद रखेगा।

फोटो गैलरी

बिहार बिज़नेस कनेक्ट 2024

बिहार बिज़नेस कनेक्ट 2024

कजरा, लखीसराय में सीएमडी, बीएसपीएचसीएल का दौरा

कजरा, लखीसराय में एमडी, बीएसपीजीसीएल का दौरा

विद्युत भवन में POSH अधिनियम पर कार्यशाला

आयकर विभाग द्वारा लेखा अधिकारियों का प्रशिक्षण

पटना में आयोजित एसएलडीसी की क्षेत्रीय बैठक

गणतंत्र दिवस 2025

होली मिलन समारोह 2025

बिहार दिवस 2024

सेवानिवृत सदस्यों का आभार...

श्री प्रणव कुमार
मुख्य अभियंता, नॉ0बि0पा0डि0कं0लि0

मो. आफताब आलम
उप सचिव, नॉ0बि0पा0डि0कं0लि0

श्री संजय कुमार सिन्हा
विद्युत कार्यपालक अभियंता, बि0स्टे0पा0ट्रां0कं0लि0

श्री सुरेन्द्र प्रसाद
आप्त सचिव, बि0स्टे0पा0हो0कं0लि0

श्री शिव शंकर सिंह
कनीय विद्युत अभियंता, सा0बि0पा0डि0कं0लि0

श्री संजय कुमार सिन्हा
लेखापाल, नॉ0बि0पा0डि0कं0लि0

श्री राज देव साव
लेखापाल, सा0बि0पा0डि0कं0लि0

श्री प्रवीन कुमार ठाकुर
लेखापाल, नॉ0बि0पा0डि0कं0लि0

सेवानिवृत सदस्यों का आभार...

श्री राकेश कुमार चौधरी
बटन–पट–चालक, सा0बि0पा0डि0कं0लि0

श्री प्रीतम सिंह
प्रधान सारणी पुरुष, सा0बि0पा0डि0कं0लि0

सेख मो. नसीम
सारणी पुरुष, बि0स्टे0पा0हो0कं0लि0

श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव
कनीय सारणी पुरुष, नॉ0बि0पा0डि0कं0लि0

श्री इन्द्रदेव प्रसाद
कनीय सारणी पुरुष, सा0बि0पा0डि0कं0लि0

श्री गणेश सिंह
कनीय सारणी पुरुष, नॉ0बि0पा0डि0कं0लि0

श्री जितेन्द्र शर्मा
भंडार सहायक, नॉ0बि0पा0डि0कं0लि0

मो. परवेज अख्तर
तकनिशियन–1, सा0बि0पा0डि0कं0लि0

सेवानिवृत सदस्यों का आभार...

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह
तकनिशियन–1, बि0स्टे0पा0ट्रां0कं0लि0

श्री कंचन ठाकुर
तकनिशियन–1, बि0स्टे0पा0ट्रां0कं0लि0

श्री सुशील कुमार
तकनिशियन–1, बि0स्टे0पा0ट्रां0कं0लि0

श्री नवल किशोर झा
तकनिशियन–1, बि0स्टे0पा0ट्रां0कं0लि0

श्री सत्येन्द्र सिंह
तकनिशियन–1, सा0बि0पा0डि0कं0लि0

श्री देवेन्द्र राम
तकनिशियन–1, बि0स्टे0पा0ट्रां0कं0लि0

श्री सत्यनारायण सिंह
तकनिशियन–III, बि0स्टे0पा0ट्रां0कं0लि0

श्री खुर्शीद अनवर
प्रधान अग्रजन, बि0स्टे0पा0ट्रां0कं0लि0

सेवानिवृत सदस्यों का आभार...

मो. नसीम आलम
प्रधान अग्रजन, बि0स्टे0पा0ट्रां0कं0लि0

श्री दुर्गानन्द कुमार
अग्रजन–1, नॉ0बि0पा0डि0कं0लि0

श्री सुखदेव प्रसाद सिंह
अग्रजन–1, नॉ0बि0पा0डि0कं0लि0

श्री श्रवण कुमार
अग्रजन–1, नॉ0बि0पा0डि0कं0लि0

श्री राजेश कुमार यादव
अग्रजन–1, सा0बि0पा0डि0कं0लि0

श्री शिव नारायण महतो
अग्रजन–1, सा0बि0पा0डि0कं0लि0

श्री रामईश्वर राम
प्रधान विद्युतज्ञ, सा0बि0पा0डि0कं0लि0

श्री चन्द्रशेखर सिंह
विद्युतज्ञ, सा0बि0पा0डि0कं0लि0

सेवानिवृत सदस्यों का आभार...

श्री अरुण कुमार सिंह
विद्युतज्ञ, सा0बि0पा0डि0कं0लि0

श्री सुमेश्वर प्रसाद
रोकड़ रक्षक, सा0बि0पा0डि0कं0लि0

श्री बैजनाथ प्रसाद यादव
चौकीदार, सा0बि0पा0डि0कं0लि0

श्री अखिलेश मिश्रा
चौकीदार, सा0बि0पा0डि0कं0लि0

श्री नागेन्द्र प्रसाद चौधरी
दरवान, सा0बि0पा0डि0कं0लि0

श्री लखन सिंह
अदक्ष खलासी, सा0बि0पा0डि0कं0लि0

श्री अवधेश कुमार सिंह
ब्रड्रामा मशीन चालक, नॉ0बि0पा0डि0कं0लि0

शहर के स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए   अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे.

बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग

विद्युत संबंधी समस्याओं का समाधान अब और भी आसान !

बिजली से जुड़ी सेवाओं को आमजन तक सरलता से पहुंचाने एवं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार तत्पर

उपभोक्ता सेवा एवं सुविधा प्राप्त करने के विकल्प

सुविधा ऐप	अब अपने मोबाइल पर Suvidha App डाउनलोड करें एवं बिजली से संबंधित महत्वपूर्ण सेवाओं को प्राप्त करें।
फ्यूज कॉल सेंटर	उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए Fuse Call Centre की स्थापना की गई है।
1912 नंबर – 24x7 सेवा	बिजली से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए 1912 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें और उसका समाधान पायें।
वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत सेवा	hargharbijli.bsphcl.co.in (Grievance Portal), sbpdcl.co.in और nbpdcl.co.in की Online Complaint सुविधा से अपनी शिकायत दर्ज करें
उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम	उपभोक्ता अपनी शिकायतों का समाधान विद्युत आपूर्ति अंचलों में स्थित Consumer Grievance Redressal Forum (CGRF) के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं।
बिल सुधार कैंप	बिजली उपभोक्ताओं को बिल संबंधी समस्याओं का समाधान के लिए स्थानीय स्तर पर बिल सुधार कैंप का आयोजन किया जाता है।
सुविधा काउंटर	अपने नजदीकी सुविधा काउंटर पर जाकर भी उपभोक्ता बिजली संबंधी सेवाओं एवं समस्याओं का समाधान पा सकते हैं।
नजदीकी बिजली कार्यालय	उपभोक्ता अपने नजदीकी बिजली कार्यालय में जाकर भी अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं।

राज्य सरकार की इन सुविधाओं का लाभ उठायें और निर्बाध बिजली सेवा पायें

हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें और विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं, नीतियों और जानकारियों से जुड़ें।

जुड़े रहें, जागरूक बनें!

Facebook: www.facebook.com/BiharEnergyDept | Twitter: x.com/EnergyBihar | YouTube: www.youtube.com/@energybihar | Instagram: www.instagram.com/energybihar

हमारा आधार... ऊर्जान्वित बिहार

खबरों में ऊर्जा

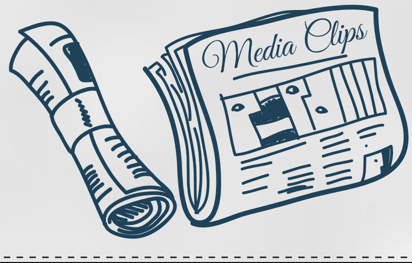

नवीकरणीय ऊर्जा में तीन हजार करोड़ का निवेश करेगा ओटू पावर ग्रुप

जागरण संवाददाता, पटना : नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने वाली ओटू पावर ग्रुप बिहार में तीन हजार करोड़ के निवेश को तैयार है। कंपनी के एग्जीक्यूटिव प्रणव पांडेय ने कहा कि वर्तमान में उनका नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक में कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में कुछ अच्छा होने वाला है।

यह आयोजन कार्य निवेशकों को बिहार आने को तैयार किया है। यहां व्यवस्था ओटी बदलती हुई दिख रही है। ऐसे में जब भी यहां निवेश को तैयार है। इसमें पहले फेज में तीन हजार ...

राजस्थान, महाराष्ट्र व कर्नाटक में कार्य कर रही है कंपनी, गया, भागलपुर एवं दरभंगा में भूमि को लेकर प्रस्ताव दिया गया है

फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में निवेश को तैयार रिगल रिसोर्सेज

रिगल रिसोर्सेज लिमिटेड के एमडी नागेंद्र सिंह बताते हैं, वह बिहार में वर्ष 2018 में पहली बार किशनगंज में 550 करोड़ का निवेश किए थे। तब यहां मक्का से स्टार्च को लेकर कोई यूनिट नहीं था। अभी उनके यहां हर दिन 780 टन मक्का की खपत हो रही है। इससे 700 लोगों को सीधे रोजगार प्राप्त हो रहा है। अब इसे बड़ा बनाने की योजना है। इसके लिए यहां 500 करोड़ और निवेश की कवायद चल रही है। इससे यहां कार्य लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। नए निवेश से हर दिन 1,600 टन मक्के की प्रोसेसिंग कर स्टार्च के साथ-साथ लिक्विड ग्लूकोज, सार्बीटोल, ... आदि का निर्माण हो सकेगा।

सूबे के 1.55 लाख किसानों को मिले बिजली कनेक्शन

उपलब्धि

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना फेज-2 के तहत कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के प्रयासों में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है।

2024-25 के लिए निर्धारित 1,50,000 कृषि विद्युत कनेक्शनों का लक्ष्य बिजली कंपनी ने दिसम्बर में ही पूरा कर लिया है। कंपनी ने चालू वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्य को पार करते हुए 1.55 लाख किसानों को बिजली कनेक्शन प्रदान कर दिया है।

बिजली कंपनी की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के फेज-2 का लक्ष्य 4.80 लाख कनेक्शन प्रदान करना है, जिसे सितंबर 2026 तक पूरा किया जाना है। यह योजना किसानों को सशक्त बनाने और कृषि उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से लागू की गई है। वितरण कंपनियों ने यह सुनिश्चित किया है कि आवेदन प्रक्रिया ...

हर घर को बिजली सब्सिडी

प्रदेश में आज लगभग क्षेत्रों में 22 से 23 घंटे तक तथा शहरी क्षेत्रों में 23 से 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है।

ऑन ग्रिड विद्युतीकरण योजना का मुख्यमंत्री ने किया शिलान्यास

पटना . मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के पहले दिन सोमवार को पश्चिम चंपारण जिले के घोटवा टोला (संतपुर सोहरिया पंचायत) से वाल्मीकिनगर क्षेत्र में 139.04 करोड़ रुपये की लागत से ऑफ ग्रिड से ऑन ग्रिड विद्युतीकरण योजना ... ऊर्जा ... ने इस ... स के ... ते हुए ... ख्यतः ... गली इलाकों में निवास कर रहे थारू जनजाति के परिवारों को ग्रिड के माध्यम से निर्बाध बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होगी. इन इलाकों में अभी विभाग द्वारा अधिस्थापित सौर ऊर्जा के संयंत्रों से बिजली मिलती है, जिसको इस परियोजना के तहत अब अंडर ग्राउंड केबल के माध्यम से जंगलों में तथा टॉवर पर गंडक नदी पार करा कर ग्रिड से बिजली उपलब्ध करायी जायेगी. इससे इन दुर्गम घने जंगल के इलाकों में भी लोगों को 24x7 बिजली उपलब्ध हो सकेगी.

एआई से होगा बिजली की खपत का आकलन

बिल वसूली और बिजली काटने का अभियान शुरू

Energy department accelerates free electricity connections for farmers

किसानों की सुविधा के साथ निरंतर संवाद बनाए रखना अनिवार्य : पंकज

ऊर्जा सचिव ने की राजस्व संग्रहण की समीक्षा, दिए निर्देश

कृषि कनेक्शन • अब तक 3.60 लाख पंप सेटों को कनेक्शन देकर चालू किया गया

किसानों को सिंचाई के लिए 2026 तक 4.80 लाख बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे, समय से पहले पूरा होगा लक्ष्य : सचिव

भास्कर न्यूज | पटना

किसानों को बिजली का कनेक्शन युद्धस्तर पर दिए जाने का असर है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 का लक्ष्य लगभग तीन माह पहले पूरा होने की ओर है। ऊर्जा विभाग के सचिव ने रविवार को यह जानकारी दी। चौथे कृषि रोड मैप के अंतर्गत प्रतिवेदित राज्य में कृषि कार्य के लिए डीजल चालित कुल 7 लाख 20 हजार पंप सेटों में से पूर्व की योजनाओं के अंतर्गत अब तक कुल 3.60 लाख कृषि पंप सेटों को बिजली कनेक्शन दिया जा चुका है। ... द्वारा शेष 3.60 ... 1.20 हुए कुल 4.80 लाख पंप सेटों को कृषि कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। कुल 4.80 लाख बिजली कनेक्शन को माह सितंबर 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। इसमें से 1.50 लाख पंप सेटों को वित्तीय वर्ष 2024-25 में विद्युत कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 1.46 लाख किसानों को बिजली कनेक्शन दिया जा चुका है। बताया गया है कि दिसंबर में अब तक निर्धारित लक्ष्य से कहीं ज्यादा कृषि कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

युद्ध स्तर पर क्रियान्वयन

ऊर्जा सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि जिस युद्ध स्तर पर इस ... और राज्य के किसान अपनी उत्सुकता दिखा रहे हैं, यह लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया जाएगा। राज्य सरकार की सात निश्चयों में से एक, मुख्यमंत्री कृषि विद्युत सम्बद्ध योजना के तहत ऊर्जा विभाग हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। अतः विभाग द्वारा इस योजना को गहन अनुश्रवण एवं प्राथमिकता के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है।

किसानों को जागरूक करने के लिए अभियान चल रहा

सचिव ने बताया कि ऊर्जा विभाग, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड और राज्य की दोनों वितरण कंपनियों साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा स्थानीय स्तर पर कैंप एवं अन्य माध्यमों से किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यापक जागरुकता अभियान भी चलाया जा रहा है। सभी जिलों में इस योजना का लाभ लेने के लिए बिजली कनेक्शन लेने के लिए किसानों द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि किसानों को बिजली से पटवन का खर्च अब डीजल के मुकाबले 10 गुना से भी अधिक सस्ता पड़ता है।

CM Nitish Kumar starts his Vikas Yatra from Valmikinagar in West Champaran

CM Nitish Kumar inaugurates on-grid electrification project in West Champaran

उपलब्धियां बिहार ने ऊर्जा के क्षेत्र में शानदार उपलब्धियां हासिल की

बिहार में 1000 से बढ़कर 8005 मेगावाट हुई बिजली की अधिकतम मांग

सोशल मीडिया पर देखकर लोगों की शिकायतें दूर करेगी बिजली कंपनी

... | बिजली कंपनी ने सोशल मीडिया ...फॉर्म पर आने वाले शिकायतों का ...ल समाधान करने की कार्रवाई शुरू ... उर्जा विभाग के सचिव पंकज ... पाल ने उपभोक्ताओं से बिजली ...के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ... अपील की है। इसमें फेसबुक, (x), इंस्टाग्राम, यू-ट्यूब व ...फॉर्म शामिल है। इन प्लेटफॉर्म ... उपभोक्ता कंपनी से सीधे ...र सकते हैं। उन्होंने कहा कि ...या के माध्यम से शिकायत ...र समाधान प्राप्त करने की ... से अधिक आसान और ... शिकायतों का समाधान ... लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी (बीएसपीएचसीएल) की सोशल मीडिया और फ्यूज कॉल सेंटर की टीम 24x7 सक्रिय है। इसके अलावा यू-ट्यूब चैनल और यू-ट्यूब के माध्यम से भी उपभोक्ताओं को बिजली सेवाओं, ऊर्जा बचत और साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी प्रदान करने की पहल की गई है।

इन माध्यमों से शिकायत : उपभोक्ता अपनी शिकायतें x (पहले ट्विटर) पर @EnergyBihar, @BiharEnergy @SEVA_NBPDCL और @SEVA_SBPDCL को टैग करके दर्ज करा सकते हैं। वहीं फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर @EnergyBihar एवं @BiharEnergy के हैंडल को टैग कर अथवा कमेंट के द्वारा अपनी समस्या बता सकते हैं।

...र परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र में 17 कंपनियां 90 हजार करोड़ पूंजी लगाने पर सहमत

...करार : बिहार में 1.80 लाख करोड़ का रिकॉर्ड निवेश होगा

निवेशकों की मदद के लिए राज्य सरकार हमेशा तत्पर : नीतीश

संचरण प्रणाली होगी सुदृढ़ तीन नई योजनाओं को मंजूरी

■ मदुआ अनुमंडल और महंथिया प्रखंड के अमवाहन में बनेंगे 280 एमवीए क्षमता वाले दो ग्रिड सब स्टेशन

■ इन परियोजनाओं से न केवल बिजली आपूर्ति मजबूत होगी बल्कि औद्योगिक व आर्थिक विकास को भी मिलेगी गति : बिजेंद्र यादव

Energy department accelerates free electricity connections for farmers

OUR CORRESPONDENT

PATNA: Energy Department, prioritizing farmers' welfare, is rapidly providing free electricity connections for irrigation under Mukhyamantri Krishi Vidyut Sambandh Yojana. With unprecedented progress, the state is on track to achieve its annual target for agricultural connections ahead of schedule, fostering a sustainable and cost-effective solution for irrigation ...

... al 4.8 lakh pump sets, including 1.2 lakh new ones, by September 2026. For FY 2024-25, target is 1.5 lakh connections, of which 1.46 lakh connections have already been provided, surpassing expectations ahead of December's end.

Energy Secretary Pankaj Kumar Pal stated that with the current momentum and farmers' enthusiasm, the targets are likely to be achieved ...

किसानों को सस्ती बिजली देना सरकार का लक्ष्य

■ कृषि फीडर सोलराइजेशन योजना को किसानों के लिए लाभदायक बताते हुए बोले ऊर्जा विभाग के सचिव, कहा- बढ़ेगा कृषि उत्पादन

बिहार की घर-घर बिजली की योजना को केंद्र ने लागू किया

12 वर्षों में पीक लोड में 8 गुना और खपत में 5 गुना की बढ़ोतरी

भास्कर न्यूज़ | पटना

ऊर्जा विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने कहा कि बिहार में घर-घर बिजली पहुंचने की राज्य सरकार की योजना की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने देश में सौभाग्य योजना लागू की। राज्य में बिजली की अधिकतम मांग 1000 मेगावाट से बढ़कर 8005 मेगावाट हो गई। प्रति वर्ष ऊर्जा की खपत भी 70 बढ़कर 363 यूनिट बढ़ी है। यानी बिजली के पीक डिमांड में 8 गुना और खपत में 5 गुना बढ़ोतरी हुई। वे शनिवार को बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन ... से आयोजित ...

... आई। बैठक में अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल से प्रतिनिधि आए थे। इस दौरान अमीर सुबहानी, डॉ. निलेश देवरे, संजय कुमार बंगा, पदम मिश्रा आदि मौजूद रहे।

168 ग्रिड से बिजली सप्लाई

राज्य में बिजली की मांग बढ़ने के बाद वितरण व संचरण प्रणाली को दुरुस्त करने की योजना बनाई गई। ...

Bihar Business Connect: New possibilities of agreements worth Rs 90,734 cr in field of renewable energy and floating solar and pump storage projects

ALOK MISHRA

PATNA: With investment proposals and agreements worth Rs 90,734 crore in field of renewable energy in Bihar, state has taken a historic step towards sustainable development. This initiative has strengthened the state towards establishing itself as one of the leading states in the country in the field of clean energy and green future.

Bihar has a large geographical landscape of water inundated areas, which are ideal for floating solar plant projects. The use of this technology will not only help in increasing energy production but will also reduce water evaporation and conserve water sources. The main benefits include elimination of the need for land, thereby preserving agricultural land, efficient use of water sources and increased energy production, environmental protection and sustainable development.

Preliminary surveys have been completed to implement Pump Storage Scheme in Bihar. Potential locations have been identified in Durgawati (Kaimur) and Nawada districts. These projects will not only stabilize power generation but will also help in grid management.

Durgavati Reservoir (Kaimur): The structure of Durgawati reservoir makes it suitable for pump storage while Nawada: Pump storage projects can be developed between the upper and lower reservoirs.

Floating solar and pump storage schemes will usher in a new era of clean energy in Bihar. These projects will create thousands of jobs. Energy self-sufficiency of the state will increase. Carbon emissions will be reduced, which is important for environmental protection.

Meanwhile, Energy minister Bijendra Prasad Yadav said, "By utilizing Bihar's water resources and geographical location, we can bring a new revolution in renewable energy. Floating solar and pump storage schemes will help make Bihar a leader in the field of clean energy. It is also a big step towards taking the state towards energy self-sufficiency and a green future ...

Major investments [in] renewable energy sector: NTPC Green: Rs 10,000 crore solar plant, NHPC: Rs 5,5.. crore, Satluj Jal Vidyut N... (SJVN): Rs 10,000 crore ... storage project, Ash... Buildcon: Rs 9,000 crore green hydrogen project.

Green future of Bihar: The initiative will accelerate economic, industrial and environmental progress along with establishing Bihar as the green energy hub of the country. With floating solar and pump storage schemes, Bihar is set to set an example in the field of energy and environmental conservation.

The successful implementation of these agreements under Bihar Business Connect will play a historic role in the industrial ...

प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों ने 2024-25 में 17,114 करोड़ का रिकार्ड राजस्व संग्रह किया

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना : राज्य की बिजली वितरण कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 17,114 करोड़ रुपये का रिकार्ड राजस्व संग्रह किया। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में यह 13 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी है। ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि यह कीर्तिमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दूरदर्शी नेतृत्व की वजह से संभव हो पाया है।

बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की अनुषंगी कंपनियों ने पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 2005 करोड़ यानी 13.27 प्रतिशत अधिक राजस्व की वसूली कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वितरण कंपनियों द्वारा संग्रहित राजस्व 17,114 करोड़ रुपये में एनबीपीडीसीएल ने 7,937 करोड़ तथा एसबीपीडीसीएल ने 9,177 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल किया।

ऊर्जा मंत्री ने इस उपलब्धि पर बिजली वितरण क्षेत्र की दोनों कंपनियों के अधिकारियों, अभियंताओं तथा राजस्व संग्रह में लगे कर्मियों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को धन्यवाद दिया है। ऊर्जा सचिव पंकज कुमार पाल ने कहा कि वितरण कंपनियों के कार्यों को आंकने के लिए बिलिंग एवं कलेक्शन कुशलता का पैमाना है। राज्य के उपभोक्ताओं को पिछले कई वर्षों से बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय भार के निरंतर सेवा प्रदान करने में बिजली वितरण कंपनियां सफल रही हैं। इस रिकार्ड राजस्व संग्रह में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की बड़ी भूमिका रही है। इसके अलावा विभिन्न सरकारी विभागों ने भी कुल 1600 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

कृषि आधारित उद्योग की संभावना सर्वाधिक : बिजेंद्र

पटना। ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने मौके पर कहा कि बिहार में कृषि आधारित उद्योग की संभावना सर्वाधिक है। यहां पर हर साल तीन फसलें उगती हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में बिजली, सड़क और अन्य आधारभूत संरचना काफी मजबूत हुई हैं। यातायात के साधन काफी बेहतर हुए हैं। उन्होंने निवेशकों से अपील की कि बड़े पैमाने पर आप सभी यहां निवेश करें। सरकार हर सहयोग देने को तैयार बैठी है। यहां पर श्रमिकों की उपलब्धता भी कोई समस्या नहीं है।

थारू जनजाति परिवारों को ग्रिड से मिलेगी बिजली

● ऑन ग्रिड योजना का मुख्यमंत्री ने किया शिलान्यास

● 25 गांवों के 11,798 घरों को मिलेगा लाभ

पूर्वी भारत के राज्यों ने बिहार में बिजली के क्षेत्र में हुई प्रगति की सराहना की

■ पटना में हुई फोरम ऑफ रेग्युलेटर्स ऑफ ईस्टर्न स्टेट की बैठक

ऊर्जा विभाग ने सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ाई, लोगों को योजनाओं के लाभ बता रहा

विभाग का लिंक्डइन पेज लॉन्च; उपभोक्ताओं से सीधा संवाद स्थापित होगा

पटना | ऊर्जा विभाग और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड व उसकी अधीन कंपनियों ने रविवार को अपना आधिकारिक लिंक्डइन पेज लॉन्च किया। यह व्यवस्था विभाग और उपभोक्ताओं के बीच सीधा संवाद स्थापित करने में सहायक होगी। इस सोशल मीडिया पेज के जरिए ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार सरकार द्वारा किए जा रहे सुधारों और नवाचारों की जानकारी लोगों को मिल सकेगी। विभाग पहले से ही फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और पॉडकास्ट जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर सक्रिय है। यहां उपभोक्ताओं को बिजली से जुड़ी योजनाओं, सेवाओं और सूचनाओं से अवगत कराया जाता है।

विभाग व बीएसपीएचसीएल सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं और उनके लाभों की जानकारी सीधे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उपभोक्ताओं को यह बताया जाता है कि वे कैसे विभाग की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा बिजली बिल भुगतान, ऑनलाइन कनेक्शन आवेदन और अन्य डिजिटल सेवाओं के दौरान साइबर फ्रॉड से बचने के उपायों की जानकारी साझा की जाती है।

ऊर्जा सचिव ने पीरपैंती में ऊर्जा ताप घर की जमीन का किया निरीक्षण

प्रतिनिधि, पीरपैंती

थर्मल पावर प्लांट का स्थल निरीक्षण करने जाते ऊर्जा सचिव पंकज पाल व अन्य.

बिहार सरकार के ऊर्जा सचिव पंकज पाल ने रविवार को पीरपैंती पहुंच 21,400 करोड़ की लागत से बनने वाले 2400 मेगा वाट के थर्मल पावर प्लांट का स्थल निरीक्षण किया. निरीक्षण में विद्युत अधीक्षण अभियंता रितु अभिषेक, ऊर्जा विभाग के अधिकारी, अनुमंडलीय स्तर के अधिकारी, जेई शुभम कुमार, बीपीआरओ, पीरपैंती थानाध्यक्ष नीरज कुमार पुलिस जवानों के साथ चौक-चौराहा पर मुस्तैदी से डटे रहे. ऊर्जा सचिव जमीन कहां व किस परिस्थिति में है, बाउंड्री सहित अन्य कार्यों से अवगत हुए, उन्होंने बाउंड्री के चारों तरफ का भौतिक निरीक्षण किया. पीरपैंती के टुंडवा मुंडवा मौजा से मुरली पहाड़ सहित आसपास की विभिन्न ऊंचाई वाले जगहों का निरीक्षण किया. उन्होंने कई मुख्य बातों से अवगत होकर तकनीकी संभावित प्रतिवेदन तैयार करने की बात कही. उन्होंने दानापुर पहाड़ के पीछे की जमीन अधिकृत करने को लेकर भौतिक निरीक्षण किया. उन्होंने मीडिया को बताया कि थर्मल पावर प्लांट प्रारंभिक स्थिति में है, हमलोग अभी स्थल भ्रमण कर रहे है. आगे की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. भूमि अधिग्रहण में विसंगतियों को लेकर कहा कि किसानों की समस्या सक्षम पदाधिकारी के द्वारा सुना जायेगा व समझा जाएगा जो नियम संभव होगा इसपर कार्रवाई की जायेगी.

उन्होंने कहा कि जितने जमीन अधिकृत की गयी है, उक्त जमीन पर जल्द से जल्द बाउंड्री का कार्य पूरा किया जायेगा. फिलहाल तकनीकी संभावित प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा, उसके आधार पर कितने मेगावाट का प्लांट लगेगा, किस प्रकार लगेगा वह सब टेक्निकली रिपोर्ट में बताया जायेगा.

डीपीआर बनने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी. किसान चेतना व उत्थान समिति के अध्यक्ष श्रवण सिंह ने ऊर्जा सचिव को आवेदन देकर प्रस्तावित ताप बिजली घर के लिए भू-अधिग्रहण के मुआवजा वितरण में धांधली की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की. मुखिया अरविंद साह ने बाढ़ के पानी को लेकर विस्तृत जानकारी दी. मुखिया को आश्वासन मिला कि जल्द ऊर्जा ताप घर का निर्माण शुरू होगा.

ई–ऊर्जस्विनी बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कम्पनियों के वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।

हमारा आधार, ऊर्जस्वित बिहार